प्रेस विज्ञप्ति

02.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स प्रकाश वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में 169.47 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्ति की वसूली की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स प्रकाश वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर-निदेशक मनोज कुमार जैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत जांच में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिन्होंने धोखाधड़ी बैंकिंग लेनदेन और ऋण निधि के अपयोजन (डायवर्जन) के माध्यम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 234.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

ईडी की जांच में पता चला कि बढ़ाकर बताई हुई वित्तीय विवरणों और जाली दस्तावेजों के आधार पर क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के बाद धन को अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया था, जिससे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 234.57 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 199.67 करोड़ रुपये की कई संपत्तियां चार अंतरिम कुर्की आदेश के माध्यम से कुर्क की गईं, जिन्हें बाद में माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई।

जनहित की रक्षा करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के धन की वसूली सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, ईडी द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें बुलाई गईं। इसके बाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी के लिए अपना आवेदन दायर किया, जिसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर सहमति याचिका के माध्यम से समर्थन दिया गया, जिससे बैंक को संपत्तियों की वापसी के लिए न्यायिक विचार किया जा सके। 28.11.2025 को, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कलकत्ता ने कुर्क की गई संपत्तियों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वापस करने की अनुमति दी, यह मानते हुए कि बैंक बकाया राशि की वैध वसूली का हकदार है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि बकाया राशि का भुगतान किया जाए और पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णयन के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अधिशेष जमा किया जाए।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की गई नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, संपत्तियों का वर्तमान प्राप्य मूल्य 169.47 करोड़ रुपये है, जो वापसी प्रक्रिया के दौरान किए गए बाजार से जुड़े पुनर्मूल्यांकन को दर्शाता है। यह वापसी वित्तीय धोखाधड़ी से प्राप्त आय को सही दावेदारों को वापस करने, सार्वजनिक धन की वसूली सुनिश्चित करने और जटिल वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने और बैंकिंग प्रणाली की अखंडता को कायम रखने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।